RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-02 | वर्ष-3 | माह-मई 2025 | प्रकाशन तिथि- मई 2025 | रायपुर से प्रकाशित | पृष्ठ-40 | मूल्य-11/-

बस्तर

नक्सलवाद से नवचेतना की ओर

छत्तीसगढ़ के विकास का उगता सूरज

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम मुलेर

छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
भारतीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम
की संयुक्त विशेष भर्ती योजना
"बीमा सखी"
महिला बीमा अभिकर्ता
3 वर्ष तक प्रतिमाह मानदेय
1st Year Rs. 7000 P.M.
2nd Year Rs. 6000 P.M.
3rd Year Rs. 5000 P.M.
साथ ही आकर्षक
अतिरिक्त कमीशन
बीमा सखी के अन्य लाभ
पार्ट टाईम/फुल टाइम कार्य
ग्रुप बीमा, होम लोन इत्यादि
आवश्यक शर्तें : 10 वीं पास उम्र 18 वर्ष से अधिक
JOIN NOW
एलआईसी
महिला विशेष भर्ती
महिला कैरियर एजेंट के रूप में
एलआईसी से जुड़ें
Years | RS
1st | Rs. 7000/-
2nd | Rs. 6000/-
3rd | Rs. 5000/-
B.V.S.Rajkumar
{OVER FOUR DECADES OF EXPERIENCE}
L.I.C.OF INDIA, RAIPUR
अधिक जानकारी
के लिए सम्पर्क करें
98266-38002

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी

(विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में दस नवीन क्रांतियों का शुभारंभ

Pg 9

महतारी वंदन योजना का दूसरा चरण जल्द, नवविवाहिताओं का भी जुड़ेगा नाम- सीएम विष्णुदेव साय

Pg 11

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम मुलेर छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार

Pg 17

स्काई-वॉक- अधूरा सपना या भविष्य का रास्ता...?

Pg 27

पोषक तत्वों से भरपूर भिंडी, गर्मी के लिए है बेस्ट...

छत्तीसगढ़ ट्राइबल म्यूजियम सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।

आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली को संरक्षित रखने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। नवा रायपुर के अटल नगर में निर्मित राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया, जो न केवल एक भव्य भवन है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय आत्मा का जीवंत चित्रण भी करता है। इस संग्रहालय का उद्देश्य केवल आदिवासी जीवन के पहलुओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उनसे संवाद करना और उन्हें सम्मान देना भी है। मुख्यमंत्री साय ने लोकार्पण समारोह में आदिवासी परंपरा के अनुरूप द्वार पूजा और पंचतत्व पूजन कर यह संदेश दिया कि यह म्यूजियम केवल ईंट-पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि श्रद्धा और संवेदना का प्रतीक है। यह संग्रहालय प्रदेश के 43 जनजातीय समुदायों और उनकी उपजातियों की जीवनशैली, परंपराओं और संस्कृति का बहुआयामी परिचय कराता है।इस संग्रहालय की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी 14 गैलरियां हैं, जो विभिन्न जनजातीय विषयों पर केंद्रित हैं। इनमें पर्व-त्योहारों से लेकर कृषि तकनीकों, परंपरागत वाद्ययंत्रों, कलाओं, औजारों और नृत्य शैलियों तक का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, कोरवा जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन के विशेष पहलुओं को भी इसमें प्रमुखता से स्थान मिला है। डिजिटल और AI तकनीक से लैस यह संग्रहालय आधुनिकता और परंपरा का अद्वितीय संगम है। क्यूआर कोड स्कैन कर दर्शक प्रत्येक झांकी की विस्तृत जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह संग्रहालय शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी बन गया है। यह म्यूजियम केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश की युवा पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगा। साथ ही यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान भी देगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम की उपस्थिति में इस म्यूजियम का लोकार्पण यह दर्शाता है कि राज्य सरकार आदिवासी विकास को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक स्वाभिमान का नया प्रतीक बनकर उभरेगा और आने वाली पीढ़ियों को हमारी जनजातीय विरासत से जोड़ने का सेतु बनेगा। यह अभिनव पहल वास्तव में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।

आपका अपना
भूषण राव

छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में दस नवीन क्रांतियों का शुभारंभ

वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेंद्र मीणा, विभाग के अधिकारी एवं सभी जिले के जिला पंजीयक और उप जिला पंजीयक उपस्थित थे। बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने पिछले एक वर्ष में हुए सुधारों, पंजीयन दस्तावेजों की स्थिति, राजस्व प्राप्ति, स्थापना, सतर्कता प्रकोष्ठ की गतिविधियों, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति, मुदांक एवं आरआरसी प्रकरणों, ऑडिट रिपोर्ट्स तथा डाटा डिजिटाईजेशन की जिलेवार प्रगति पर चर्चा की।

मंत्री श्री ओपी चौधरी ने फील्ड स्तर पर विभागीय सेवाओं के संचालन में आ रही समस्याओं को भी सुना और तकनीकी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता के लिए शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करें और पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स व बैनर लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

राजस्व संग्रहण में पंजीयन विभाग का योगदान

पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.86 प्रतिशत की वृद्धि है। विभिन्न जिलों में दस्तावेजों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति के आधार पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शीर्ष पर रहे। इस तरह प्रदेश के राजस्व संग्रहण में पंजीयन विभाग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री श्री चौधरी ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और कार्यों को संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से करने की प्रेरणा दी।

तकनीकी मजबूती के लिए नई पहल

मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए सेटअप का पुनरीक्षण कर नए पदों का सृजन किया गया है। इससे फील्ड में काम कर रहे अमले को दस्तावेजों की गहन जांच कर पंजीयन करने में सुविधा होगी। मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लॉकर सुविधा, फेसलेस रजिस्ट्री और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन जैसे नवाचारों को तेजी से लागू करें। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को घर बैठे सुरक्षित और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।

दस नई क्रांतिकारी सुविधाएं शुरू

- मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग में आम जनता की सुविधा और दस्तावेजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए

अपने सॉफ्टवेयर में दस नई सुविधाओं को शामिल किया है

- **आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा–** पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की जा रही है।
- **ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा–** खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड की सुविधा।
- **भारमुक्त प्रमाण पत्र–** संपत्ति पर किसी भार या बंधक की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा।
- **एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली–** स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान की सुविधा।
- **व्हाट्सएप मैसेज सेवा–** पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम जानकारी व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- **डिजी लॉकर सुविधा–** रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।
- **ऑटो डीड जनरेशन–** दस्तावेजों का स्वत: ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण।
- **डिजी डॉक्यूमेंट सेवा–** शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।
- **घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा–** ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराये जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रूपए लिये जाने का प्रावधान है।
- **स्वतः नामांतरण सुविधा–** रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की सुविधा होगी। यह आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, इससे पक्षकारों को विचौलियों से मुक्ति के साथ नामातंरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। समय और श्रम के साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।

मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन सभी नवाचारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए और आम जनता को उनकी सुविधाओं के बारे में जागरूक करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि विभाग की पारदर्शिता और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें - मंत्री श्री चौधरी

मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करें, पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और विभागीय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरी रखते हुए कार्य करें। नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने हेतु विभाग को नई तकनीकों के साथ लगातार अपडेट किया जाए।

डिप्टी सीएम साव बोले-अब नहीं रहेगा कोई भी घर कच्चा बिलासपुर में खोज-खोज कर बनाएंगे पक्का मकान, मोदी की हर गारंटी होगी पूरी

बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, राज्य सरकार मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किया जो अब पूरा हो रहा है। गरीब परिवारों का एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार सर्वे के जरिए खोज खोज कर उनका आवास पक्का बनाने के लिए कमर कसी हुई है।

दरअसल, बेलतरा विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव ने विकास के लिए 21 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की लागत के 44 विकासकार्यों का भूमिपूजन किया। जिसमें गोंदइया में 12 करोड़ 1 लाख की लागत से एनीकेट निर्माण, अरपा नदी में जल संसाधन विभाग के एक करोड़ 69 लाख की लागत से डाइक निर्माण और लगरा में दो करोड़ 81 लाख की लागत से एनीकेट प्रोटक्शन वॉल का निर्माण शामिल है।

हर काम साय साय गति से पूरा हो रहा

अरुण साव ने कहा कि, ष्टरूसाय के नेतृत्व में हर काम साय साय गति से पूरे हो रहे हैं। हमने पुराना धान का बोनस भी 3716 करोड़ अटल की जयंती पर 2023 में दिया। महतारी वंदन का 1 हजार रुपए हर महीना दे रहे हैं। अब तक 15 किस्त दिए जा चुके हैं। महिलाएं सोची भी नहीं थी की राशि मिलेगा। लेकिन, उनका सपना हमारी सरकार ने पूरा किया। एक तरफ जहां मोदी मुफ्त में चावल लोगों को दे रहे हैं। वहीं, विष्णु देव साय की सरकार महिलाओं को नगद सहायता कर रही हैं। महिलाओं के दोनों हाथों में लड्डू वाली फायदा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आतंकवादियों ने जहां हमारे लोगों की धर्म पूछ कर मारा। हम उनके घर घुसकर उनके कर्म पूछ कर हमले किए हैं। आज पड़ोसी देश हमारी सेना के पराक्रम के सामने घुटने टेक दिए।

डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुलझा रही है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और विष्णु देव साय की सरकार इसे विकसित स्वरूप में गढ़ने का काम कर रही है। राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में गांव गरीबों किसानों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है।

मोदी की गारंटी पूरा कर रहे

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की धारा बह रही है। यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 164 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 करोड़ के विकास कार्य अभी चल रहे हैं। हमारी सरकार की कथनी और करनी एक है। मोदी की गारंटी के रूप में हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है।

विष्णु देव सरकार के नेतृत्व में बिना भेदभाव के समाज के सभी तबकों का विकास समान रूप से हो रहा है। उन्होंने सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जनपद पंचायत बिल्हा के अध्यक्ष राम कुमार कौशिक, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, मोहित जायसवाल, गोंदइया की सरपंच हेमलता सक्सेना समेत बड़ी संख्या में आसपास के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और ग्रामीण किसान जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें- साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान न्यायिक व्यवस्था को जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि ÷दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रिया को सहज और तेज़ किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से आदिवासी अंचलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जहाँ आवागमन की कठिनाइयों के चलते लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप , विधायक श्री चैत राम अट्ठामी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह आयुक्त जनसंपर्क डॉ. श्री रवि मित्तल, संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ÷सुशासन तिहार÷ सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार 2025 तीन चरणों में चलाया जा रहा है, और तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में हमने मोदी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से लागू किया है, जिससे आमजन में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई हुई है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रहवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएं ताकि ये युवा मुख्यधारा में आत्मविश्वास से लौट सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय अंचलों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने 1460 पंचायतों में शुरू हुए अटल सेवा केंद्रों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य बस्तर क्षेत्र खनिज एवं वनोपज संपदा से समृद्ध है। यहां के रहवासियों की आय संवृद्धि और उन्हें विकास की मुख्यधारा से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। बस्तर के समग्र विकास को सुनिश्चित कर बस्तर ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ और देश को मार्च 2026 तक बस्तर से माओवाद का समूल उन्मूलन करेंगे। उन्होंने

वनोपज संग्रहण , प्रसंस्करण और खेती को जनजातीय समुदाय के समृद्धि के जरूरी निरूपित करते हुए खेती-किसानी को बढ़ावा देने सहित सिंचाई के साधनों के विकास और कृषि के आनुषांगिक गतिविधियों मछलीपालन, पशुपालन, बकरापालन, सूकरपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। वहीं बस्तर में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर फोकस कर इसके जरिए रोजगार को बढ़ावा देने कहा।

मुख्यमंत्री ने बस्तर के ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने नियद नेल्लानार योजनांतर्गत सम्बन्धित क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया तथा अन्य विकास कार्यों को टीम भावना के आगे बढ़ाते हुए जन सेवा में जुटे रहने के निर्देश दिए। वहीं शासन की सभी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किए जाने तथा व्यक्तिमूलक योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सेचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बीजापुर के कलेक्टर ने जानकारी दी कि समर कैम्प और बाल शिक्षा मित्र कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार (हाई स्कूल में 10त्न और हायर सेकेंडरी में 4त्न वृद्धि) पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राइस मिल लगाने के लिए दी गई रियायतों की जानकारी दी और स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊंची भूमि में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि कृषक आय में वृद्धि हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि टीम भावना से कार्य करें और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में डीजीपी श्री अरुण देव गौतम ने भी समन्वयपूर्ण कार्यशैली पर बल दिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बलौदाबाजार-भाटापारा की अग्रणी भूमिका- किसानों को मिली आर्थिक संबल की ताकत...

भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना के तहत पात्र कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों में वार्षिक ?6000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने इस योजना के क्रियान्वयन में राज्यभर में प्रथम स्थान प्राप्त करके एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बलौदाबाजार-भाटापारा- प्रदेश में प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 1,34,269 किसानों को ?31.38 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की गई। यह न केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि है, बल्कि यह जिले के कृषक परिवारों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुई है।

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

PM-KISAN योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत-

- प्रत्येक पात्र किसान को वर्ष में ?6000 की राशि दी जाती है।
- यह राशि तीन समान किश्तों (?2000 प्रत्येक) में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- इसका उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सहायता देना है।

बलौदाबाजार-भाटापारा में सफल क्रियान्वयन की कुंजी- प्रशासनिक संकल्प और नवाचार

इस जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन का मुख्य श्रेय कलेक्टर दीपक सोनी के नेतृत्व को जाता है, जिनके द्वारा चलाए गए पीएम किसान सैचुरेशन कैम्पेन और सुशासन तिहार समाधान शिविर ने गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचाने का कार्य किया। इन अभियानों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

कुछ प्रमुख पहलें

- ग्राम स्तरीय शिविरों के माध्यम से किसानों को योजना की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
- किसानों को ई-केवायसी, आधार लिंकिंग, और डीबीटी सक्रियता में सहायता दी गई।
- विकासखंड कार्यालयों और मैदानी अधिकारियों की टीमें गांवों में पहुंचकर किसानों के खातों की स्थिति की जांच और मार्गदर्शन कर रही हैं।

कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट किया, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

किसानों के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेज

उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने योजना से जुड़ी पात्रता और पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं भूमिधारी कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम पर कृषि भूमि हो और जो स्वयं उसमें खेती करते हों।

आवश्यक दस्तावेज

1. पीएम किसान स्वघोषणा पत्र
2. आधार कार्ड
3. राशन कार्ड
4. बी-1 या ऋण पुस्तिका की छायाप्रति
5. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
6. डीबीटी सक्रिय बैंक पासबुक की कॉपी

किसान PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर सीएससी (CSC) केंद्रों की मदद से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन के बाद, सभी दस्तावेजों को 7 दिन के भीतर संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है।

तकनीक और डिजिटल जागरूकता का समावेश

आज के डिजिटल युग में योजनाओं के लाभ का पूर्ण उपयोग तभी संभव है जब किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में-

- डिजिटल जागरूकता अभियानों द्वारा किसानों को ऑनलाइन पंजीयन, मोबाइल अपडेट, और डीबीटी सक्रियता की जानकारी दी जा रही है।
- ई-केवायसी अपडेट कराने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए हैं।
- बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नए खाते खुलवाने तथा पुराने खातों की डीबीटी जांच में सहायता की जा रही है।

भविष्य की रणनीति- 100% सैचुरेशन का लक्ष्य

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के हर पात्र किसान को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई हैं-

- निरंतर नए पंजीयन और पुराने खातों की समीक्षा।
- हर ब्लॉक में नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- साप्ताहिक प्रगति समीक्षा बैठकें।
- मासिक ट्रैकिंग रिपोर्ट के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण।
- किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान।

जन-सहभागिता और ग्राम पंचायतों की भूमिका

ग्राम पंचायतें और कृषि विभाग योजना के सफल क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किसानों को दस्तावेज़ों की जानकारी देने, सत्यापन करवाने और प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं।

किसानों के लिए सीधा संदेश

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के प्रशासन की ओर से किसानों से यह अपील की गई है कि-

- अपने दस्तावेज अपडेट रखें।
- योजना से जुड़ी जानकारी के लिए ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें।

- समय-समय पर आने वाले शिविरों में भाग लें और अपना ई-केवायसी अपडेट कराएं।
- अपने बैंक खाते को डीबीटी के लिए सक्रिय रखें।

आत्मनिर्भर कृषक, सशक्त भारत की ओर कदम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में भी अग्रसर करती है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की यह उपलब्धि साबित करती है कि यदि प्रशासनिक संकल्प, जन-सहभागिता, और डिजिटल समावेश साथ आएं, तो कोई भी योजना जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचाई जा सकती है।

- यह मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों, बल्कि देशभर के प्रशासनिक इकाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है।
- हर खेत तक पहुंचे सरकार की मदद ङ्क यही है आत्मनिर्भर किसान का सही रास्ता।

महतारी वंदन योजना का दूसरा चरण जल्द, नवविवाहिताओं का भी जुड़ेगा नाम- सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने संकेत दिया है कि बहुत जल्द महतारी वंदन योजना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है

प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत अचानक मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे. अचानक प्रदेश के मुखिया जब इस गांव में पहुंचे तो गांव में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला और लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़े. ग्रामीणों ने आस-पास लगे फूलों से सुन्दर गुलदस्ता तैयार कर उनका स्वागत किया.

प्रदेश के मुखिया ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई. सीएम ने चौपाल की शुरुआत भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ की. गांव के सरपंच को अपने पास बिठाया और पंचायत में विकास कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के ि यान्वयन और समस्याओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री के आगमन की खबर पाकर आसपास के कोलियारी और कुवांरपुर पंचायत के साथ ही कई गांवों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण माथमौर पहुंचे थे. जिन्होंने अपनी समस्याएं और मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखी.

नई बहुओं को भी महतारी वंदन योजना जल्द

इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने राशन दुकान संचालन, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर ग्रामीणों से फीडबैक लेने के साथ ही उन्होंने महिलाओं से पूछा कि, क्या उन्हें हर महीने 1 हजार रुपये की राशि समय पर मिल रही है या नहीं इसकी भी जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो नवविवाहित महिलाएं इस योजना के पात्र हैं उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा. वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने के लिए कहा गया है.

कुवांरपुर में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई जानने के साथ ही मुख्यमंत्री ने माथमौर और उसके आसपास के गांवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की. उन्होंने कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फुलझर से चंदेला, तिलौली से दर्रीटोला, सनबोरा से पण्डो, कुवांरपुर से गाजर और पटपर टोला से चंदेला तक नई सड़कों के निर्माण कराए जाने की बात कही है.

मुख्यमंत्री में कुवांरपुर में नायब तहसीलदार कार्यालय के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बंदोबस्त कैंप आयोजित करने एसडीएम को निर्देश दिया. माथमौर में सामुदायिक भवन की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीणों को सामाजिक आयोजनों और बैठकों के लिए एक स्थायी सुविधा मिल सकेगी.

जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल निर्माण की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है. जिससे इस आदिवासी अंचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. इस दौरान उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवांरपुर में पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य की करियर प्लानिंग पर बात करते हुए गांव में स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली. इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. भी मौजूद थे.

10वीं 12वीं बोर्ड के बच्चों से बात करते सीएम साय

सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर- वहीं मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम अमोरा में भी सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने भाग लिया. इस समाधान शिविर में 14 ग्राम पंचायतों के 4182 आवेदनों का निराकरण किया गया. 344 शौचालयों की मंजूरी भी मिली.शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सहायता दी गई. मनरेगा के अंतर्गत 7 लोगों को पशु शेड निर्माण की मंजूरी मिली. 33 लोगों को नए जॉब कार्ड और 54 को नए राशन कार्ड दिए गए. 61 लोगों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किए गए. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई.

महतारी वंदन योजना के 2 हितग्राहियों को शॉल और श्रीफल दिए गए. शिक्षा विभाग ने 9 बच्चों को श्रवण यंत्र, लो विजन किट, ब्रेल लिपि किट, एमआर किट और व्हील चेयर वितरित किए. कृषि क्षेत्र में 6 किसानों को पावर स्प्रेयर दिया गया. 5 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1.80 लाख रुपए का चेक मिला. 10 किसानों को केसीसी के तहत 9.34 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया.

मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच है कि जनता को कोई परेशानी न हो. मुख्यमंत्री खुद समाधान शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम मुलेर

छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय का ग्रामीणों ने महुआ, आमपत्ती से बने पारंपरिक हार और गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम का भी छिंद पत्तों से बने पारंपरिक गुलदस्तों से अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण तथा गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली दंतेवाड़ा की छात्रा रमशिला नाग से भेंट की, उसे पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री श्री साय का यह दौरा न केवल सुशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत मुलेर विकास की नई इबारत लिख रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन ने इस गांव को सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सेवा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

बड़े बचेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुलेर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर स्थित है। कुल 112 परिवारों में 474 लोग निवासरत हैं, जिनमें 100 प्रतिशत माड़िया जनजाति के लोग हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केन्द्र (बाल्केपारा व पटेलपारा) संचालित हैं। गांव में 6 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है। इसका उपयोग खेती के साथ-साथ किराए पर भी किया जा रहा है। बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राशन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। गांव में सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग की व्यवस्था है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ग्राम मुलेर में महिलाएँ महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है। मुलेर ग्राम पंचायत सुदूर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुँच और सुचारू क्रियान्वयन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता से विकास की दिशा में सतत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

बस्तर- नक्सलवाद से नवचेतना की ओर- छत्तीसगढ़ के विकास का उगता सूरज

छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित बस्तर, लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी रही है कि यह क्षेत्र दशकों तक नक्सलवाद की आग में झुलसता रहा। बस्तर की छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अशांत और असुरक्षित क्षेत्र के रूप में उभरी, जिससे यहां विकास, निवेश और पर्यटन जैसे पहलुओं को गहरा आघात पहुंचा।

अब जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में यह दावा किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में बस्तर राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, तब यह सवाल उठता है ङ्क क्या यह महज एक राजनीतिक बयान है या सचमुच एक परिवर्तनकारी योजना का हिस्सा? इस लेख में हम इस कथन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि बस्तर कैसे नक्सलवाद की राख से उभरकर विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

नक्सलवाद- बस्तर पर पड़ा सबसे गहरा धब्बा

बस्तर का इतिहास बताता है कि यहां की भूमि क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमि रही है। लेकिन 1980 के दशक से यहां नक्सलवादी गतिविधियों ने धीरे-धीरे अपने पैर पसारने शुरू किए। पहले यह आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन, धीरे-धीरे हिंसा, अपहरण, सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ और आम जनता में भय फैलाने वाले गतिविधियों में तब्दील हो गया।

पिछले कई दशकों में हजारों सुरक्षाकर्मी और निर्दोष नागरिक इस हिंसा का शिकार हुए। नक्सलियों के डर से विकास के पहिए रुक गए, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले हुए, और स्थानीय जनजीवन एक प्रकार की सामाजिक कैद में जीने को मजबूर हो गया।

सरकार की बदलती रणनीति और निर्णायक रुख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुआयामी और समन्वित रणनीति अपनाई है। इसके अंतर्गत न केवल सैन्य कार्रवाई को सशक्त किया गया, बल्कि आत्मसमर्पण, पुनर्वास और विकास को प्राथमिकता दी गई है।

1. संयुक्त कार्य बल

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमाओं से सटे होने के कारण बस्तर में नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया है। यह बल अंतर-राज्यीय समन्वय के साथ नक्सलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने से रोकने के लिए काम करता है।

2. आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025

सरकार की 'नक्सली आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025' का उद्देश्य हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को बेहतर पुनर्वास, आर्थिक सहायता, जमीन, और नौकरी के अवसर उपलब्ध

कराना है। इससे अब तक 1300 से अधिक नक्सलियों ने मुख्यधारा में वापसी की है।

3. नियद नेल्लनार योजना

'नियद नेल्लनार' योजना के अंतर्गत सरकार सुरक्षा शिविरों के आसपास के गांवों में 52 योजनाएं और 31 सामुदायिक सुविधाएं लेकर पहुंच रही है। बिजली, सड़क, पानी, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, बैंकिंग सेवाएं ङ्क इन सबका विस्तार अब सुदूर बस्तर तक हो रहा है।

विकास का नया एजेंडा- बस्तर को छत्तीसगढ़ का मुकुटमणि बनाना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर को अगले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ का मुकुटमणि बनाने का जो संकल्प लिया है, उसका आधार केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि व्यापक विकास है। यह विकास बहुआयामी है ङ्क जिसमें औद्योगिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी पक्षों को शामिल किया गया है।

1. पर्यटन का विस्तार

बस्तर की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्राकृतिक संपदा है ङ्क चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर घाटी, तीरथगढ़ झरना, दंतेवाड़ा मंदिर, गुफाएं और घने वन ङ्क इन सबको पर्यटन केंद्रों में बदला जा रहा है।

होमस्टे परियोजनाएं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे स्थानीय आदिवासियों को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यटकों को असली छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अनुभव भी। बस्तर के दो स्थल ङ्क धुड़मारस गांव और कांगेर घाटी ङ्क अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर दर्ज हो चुके हैं।

2. लघु वनोपज आधारित उद्योग

बस्तर के घने जंगलों में लाख, तेंदू पत्ता, चिरौंजी, महुआ जैसे दर्जनों वनोपज उपलब्ध हैं। सरकार इनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर रही है। इससे न केवल कच्चा माल वहीं उपयोग होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा।

3. पशुपालन और कृषि आधारित मूल्य संवर्धन

सरकार अब पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाजार सुविधा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।

खनन पर उठती चिंताओं पर सरकार का जवाब

कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने आशंका जताई है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर में बड़े पैमाने पर खनन शुरू किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री ने इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार जबरन कोई उद्योग नहीं लगाएगी। नई औद्योगिक नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी परियोजना को जनसुनवाई और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, टिन, सोना और लिथियम जैसे खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं, लेकिन इनका उपयोग सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि बात के बदले बात, गोली के बदले गोली की नीति केवल हिंसक नक्सलियों के लिए है, न कि आम नागरिकों के लिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा

विकास केवल औद्योगीकरण से नहीं आता, यह तब आता है जब समाज का हर वर्ग अपने अधिकारों, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच बना सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है।

नई स्कूल भवन, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे उपाय लिए जा रहे हैं। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था की गई है, और ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं दी जा

रही हैं।

बस्तर में सड़कें बन रही हैं, पुल-पुलिया निर्माण हो रहा है, और गांवों को बिजली, इंटरनेट और बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। ये सभी प्रयास समावेशी विकास की नींव को मजबूत कर रहे हैं।

सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय गौरव

बस्तर की संस्कृति उसकी आत्मा है। यहां की जनजातियां जैसे मुरिया, माड़िया, बटरा, हल्बा आदि की जीवनशैली, लोकगीत, नृत्य और धार्मिक आस्थाएं अत्यंत समृद्ध हैं।

सरकार इन सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बस्तर महोत्सव, लोक संस्कृति केंद्र, आदिवासी संग्रहालय और भाषा-संवर्धन केंद्रों की स्थापना कर रही है।

विकास का अर्थ केवल सड़कें और फैक्टरी नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को सशक्त बनाना भी है, मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य इस सोच को दर्शाता है।

बस्तर के भविष्य की कल्पना

अगर वर्तमान योजनाएं और संकल्प इसी गति से कार्यान्वित होते रहे, तो आने वाले दशक में बस्तर केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक आदर्श मॉडल बन सकता है ङ्क जहां सुरक्षा, विकास, प्रकृति और संस्कृति का संतुलन हो।

बस्तर भविष्य में

एक प्रमुख पर्यटक स्थल हो सकता है,

वनोपज आधारित निर्यात केंद्र बन सकता है,

सांस्कृतिक पर्यटन और अनुसंधान का केंद्र बन सकता है,

और सबसे अहम ङ्क यह साबित कर सकता है कि हिंसा से शांति की ओर बदलाव संभव है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बस्तर के लिए जो विकास दृष्टि है, वह केवल एक राजनीतिक रोडमैप नहीं, बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। नक्सलवाद के खात्मे की राह कठिन अवश्य है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने सुरक्षा, संवाद, पुनर्वास और विकास ङ्क इन चारों स्तंभों को समन्वित किया है, वह निश्चित ही बस्तर के लिए आशा की नई किरण है। बस्तर अब केवल संघर्ष की भूमि नहीं, बल्कि संभावना, समृद्धि और संस्कृति की भूमि बन सकता है- बशर्ते विकास के इस रास्ते पर सरकार और समाज दोनों साथ चलें।

समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन की सच्ची पहचान- मंत्री राजवाड़े

छत्तीसगढ़ सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी म में सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 16 ग्राम पंचायतों से आए हजारों ग्रामीणों की 2118 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर कीर्तिमान स्थापित किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शिविर में आए ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और सहभागी शासन व्यवस्था को मजबूत बना रही है। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन की सच्ची पहचान है।

शिविर के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने मोर गांव मोर पानी और जल शक्ति अभियान के तहत उपस्थित जनसमुदाय को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। वर्षा जल संचयन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और सोखता गड्ढों की उपयोगिता बताते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है।

समाधान शिविर में गोद भराई कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने महिलाओं को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए मातृत्व का सम्मान किया। नवजातों को अपने हाथों से खिलाते हुए उन्होंने माताओं के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इसके साथ ही किसानों को ऋण पुस्तिकाएं वितरित करते हुए उन्होंने कहा, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

शिविर में पशुधन विकास विभाग की चलित इकाई द्वारा एचएसबीक्यू, गलघोंटू और एकटंगीया जैसे रोगों का सघन टीकाकरण कर पशुधन को बीमारियों से सुरक्षा दी गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल श्री रमेन डेका से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों ने की मुलाकात...

श्री डेका ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान और पांच-पांच हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी

राज्यपाल श्री रमेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लेकर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले रायपुर जिले के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। श्री डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और पांच-पांच हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी।

इस अवसर पर श्री डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया और कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। वे जिस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें। अध्ययन के साथ-साथ योग, ध्यान एवं खेल गतिविधियां भी करें। अपने माता-पिता और गुरूजनों का सम्मान करें। मानवीय गुणों और परस्पर सहयोग की भावना के साथ-साथ अपने आस-पास के प्रति भी जागरूक रहते हुए जीवन का आनंद उठाएं।

इस अवसर पर उपस्थित विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और प्रदेश का नाम रोशन करें।

कार्यक्रम में श्री डेका ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं की कुमारी साई संजना, नमन कुमार ठाकुर, केतन साहू, कुमारी खुशबू सेन, कुमारी पूर्वी साहू, महक, राम सोनी, कुमारी नेहा चक्रधारी, कुमारी काव्या वर्मा, कुमारी दिव्या तिवारी, चित्रांश देवांगन, को सम्मानित किया। इसी तरह कक्षा 12वीं के प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी पल्लवी वर्मा, कुमारी रूचिका साहू, कुमारी कीर्ति यादव, कुमारी रूची कल्यानी, कुमारी भूमिका देवांगन को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में राज्यपाल की संयुक्त सचिव सुश्री निधि साहू, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर डॉ. विजय खंडेलवाल सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी तथा पालकगण उपस्थित थे।

रजक समाज का परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव में रहा है महत्वपूर्ण योगदान - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा रजक समाज,जिनका परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। रजक धोबी समाज हमारे गांवों के उन समुदायों में से एक हैं जिन्हें हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है। इसी हुनर से वे रोजगार प्राप्त करते रहे हैं। नये जमाने में इस हुनर को और निखारने की जरूरत है। हम परंपरागत काम को कैसे आधुनिक बना सकते हैं, रोजगार के नये अवसरों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी बोर्ड के माध्यम से पहल करें। आप जो रास्ता तय करेंगे, उसमें हमारी सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी।

श्री साय ने आगे कहा रजक समाज परंपरागत रूप से श्रम, सेवा और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं जहां रजक समुदाय के लोग निवास नहीं करते है। हर गांव में रजक समाज से जुड़े व्यक्ति निवास रहते है जिनका समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर और सम्मानजनक भागीदारी मिले।

हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और वंचित समुदायों को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय,और स्वावलंबन के सभी साधन उपलब्ध कराएं। यही सामाजिक न्याय है। यही समरसता का मार्ग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कौशल उन्नयन को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर उनका स्किल डवलपमेंट से स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

रजककार विकास बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि हम इस समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानें, उनके लिए योजनाएँ बनाएं,और उन्हें विकास की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ जोड़ें। मुझे विश्वास है श्री प्रहलाद रजक जी अपने सुदीर्घ अनुभव से समाज की अपेक्षाओं निश्चित ही खरा उतरेंगे। उनकी यह नियुक्ति केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता,समान अवसर और सामाजिक न्याय पर आधारित है।

स्काई-वॉक- अधूरा सपना या भविष्य का रास्ता...?

शहर बदलते हैं, जब सोच बदलती है।
विशेष संवाद, रायपुर योजना प्रकोष्ठ

स्थान-	रायपुर
प्रोजेक्ट शुरू-	2017
पुन: प्रारंभ-	2025
नवीन लागत-	37.75 करोड़
निर्माण एजेंसी-	PSS कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. रायपुर
पृष्ठभूमि-	एक अधूरा अध्याय

रायपुर स्काई-वॉक प्रोजेक्ट की नींव 2017 में रखी गई थी। उद्देश्य था शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों—शास्त्री चौक, जय स्तंभ चौक, और अंबेडकर अस्पताल—को एक ऊंचे, सुरक्षित और आधुनिक मार्ग से जोड़ना। लेकिन यह सपना तकनीकी, प्रशासनिक और राजनीतिक पेचिदगियों में उलझकर अधूरा रह गया।

रिपोर्ट कार्ड- 8 साल बाद क्या हाल है?

घटक	स्थिति
स्टील संरचना	संतोषजनक, मरम्मत योग्य
रेलिंग/फ्रेम	कई स्थानों पर चोरी
पेंटिंग व फिनिशिंग	अधूरी
गर्डर व स्लैब	आंशिक रूप से तैयार
पर्यावरणीय सुरक्षा	नई योजना में शामिल

अब क्या नया है?

12 स्थानों पर एस्केलेटर
दो अतिरिक्त सीढ़ियाँ
लिफ्ट से अंबेडकर और छ्यस् अस्पताल को जोड़ा जाएगा
शास्त्री चौक पर रोटरी सिस्टम
टाइल फर्श व पॉली-कार्बोनेट छत
RCC स्लैब व स्टील रेलिंग

विज़न 2026-हर कदम, सुरक्षित और आधुनिक

राज्य सरकार का दावा है कि यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि एक अर्बन मोबिलिटी मॉडल है। स्मार्ट सिटी के लिए यह एक प्रेरक आधार बनेगा, जिसमें पैदल यात्रियों को सुरक्षा, सुविधा और संरक्षित मार्ग मिलेगा।

जन आवाज़

यह प्रोजेक्ट शहर के ट्रैफिक को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। अगर समय पर पूरा हुआ तो ये रायपुर के विकास की दिशा बदल सकता है।

- संदीप ठाकुर, सिविल इंजीनियर, रायपुर

पिछली बार तो राजनीति के चक्कर में काम रुका, अब कम से कम पूरा हो तो सही। मरीजों को बहुत दिक्कत होती है।

- निशा यादव, परिचारिका, अंबेडकर अस्पताल

विश्लेषण बॉक्स- यह प्रोजेक्ट क्यों है अहम?

40,000+ पैदल यात्रियों को राहत
अस्पतालों के बीच सुगम कनेक्टिविटी
पर्यावरण संरक्षण (ट्रैफिक कम, प्रदूषण में गिरावट)
स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

चुनौतियाँ

पुराना ढांचा जर्जर न हो जाए
चोरी व टूट-फूट को रोका जाए
निर्माण गुणवत्ता पर सख्त निगरानी
समय-सीमा का कड़ाई से पालन

रायपुर का स्काई-वॉक प्रोजेक्ट एक शहरी विकास का प्रतीक बन सकता है, अगर यह अब बिना रुकावट और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इसके लाभ बहुआयामी होंगे — यातायात, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण और नागरिक सुविधा सभी स्तरों पर। यह सिर्फ एक पुल नहीं, भविष्य की ओर बढ़ता रायपुर है।

हॉकी का हब बना जांजगीर- छोटे शहर से निकल रहे बड़े खिलाड़ी

(एक प्रेरणादायक रिपोर्ट)

छत्तीसगढ़ का जांजगीर-चांपा ज़िला इन दिनों केवल गर्मी की तपिश के लिए नहीं, बल्कि हॉकी की ऊष्मा और उत्साह के लिए भी चर्चा में है। जहां अधिकांश बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ आराम और मनोरंजन का समय होती हैं, वहीं जांजगीर के भाठापार इलाके में बच्चे इन छुट्टियों में पसीना बहा रहे हैं — अपने सपनों को आकार देने के लिए। ये बच्चे किसी बड़े शहर या अमीर परिवार से नहीं, बल्कि मेहनतकश मजदूर परिवारों से आते हैं, और उनके हाथों में कलम के साथ अब हॉकी स्टिक भी है।

मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान- सपनों की नर्सरी

भाठापार में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान केवल एक खेल का मैदान नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सीमित संसाधनों में भी असीम क्षमताएं रखते हैं। इस मैदान में साल भर अभ्यास चलता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यहां विशेष 30 दिवसीय हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

इस शिविर में 50 से अधिक बालक-बालिकाएं भाग ले रहे हैं, जिनकी उम्र पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक है। इनमें से कई बच्चे नेशनल और स्टेट लेवल पर अपना जौहर दिखा चुके हैं। अब तक इस मैदान से 300 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के और 700 से अधिक राज्य स्तरीय खिलाड़ी निकल चुके हैं।

खेल का नया नजरिया

पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो हो जाओगे खराब — इस पुराने सोच को जांजगीर के बच्चे और कोच मिलकर तोड़ रहे हैं। अब पढ़ाई और खेल को बराबर महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि इन बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा अब सामने आ रही है।

शिविर में न केवल हॉकी की तकनीकी बारीकियां सिखाई जाती हैं, बल्कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से भी अवगत कराया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा, कैरियर गाइडेंस, और देशभक्ति जैसे मूल्य भी इन्हें साथ-साथ सिखाए जा रहे हैं।

खिलाड़ियों की जुबानी

बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास और सपनों की चमक साफ दिखाई देती है।

पूजा, जो अब नेशनल खिलाड़ी बन चुकी हैं, कहती हैं-

दीदी को खेलते देखा तो मुझे भी हॉकी खेलने की इच्छा हुई। अब दो साल हो गए हैं हॉकी खेलते हुए।

गुंजन सूर्यवंशी, जिनका चयन नेशनल गेम्स में हो चुका है, बताती हैं-

कोच सर ने हमें शूज, ड्रेस और दूसरी जरूरी सुविधाएं दी हैं। हमारी हर मदद हो रही है।

धनंजय कहरा और मानस सोनवान जैसे अन्य खिलाड़ी भी ड्रिब्लिंग, पासिंग और टीम प्ले जैसी तकनीकों में खुद को निखार रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगता है।

कोच गोपेश्वर कहरा- जुनून से प्रेरणा तक

इस हॉकी क्रांति के केंद्र में हैं गोपेश्वर कहरा — एक ऐसा नाम जिसने न केवल अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, बल्कि दूसरों के सपनों को साकार करने का भी बीड़ा उठाया। पीएससी की मेंस परीक्षा में सफल होने के बाद भी चयन नहीं होने पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को खेल को समर्पित कर दिया और आज उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों बच्चे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जांजगीर-चांपा का नाम रोशन कर रहे हैं।

गोपेश्वर कहते हैं,- हमें बच्चों की क्षमता पर भरोसा है। संसाधन भले सीमित हों, लेकिन अगर मार्गदर्शन सही हो, तो प्रतिभा किसी भी मंच पर चमक सकती है।

कच्चे मैदान से बड़े ख्वाब तक?

इस शिविर की एक और खास बात यह है कि बच्चे मुरुम के कच्चे मैदान में अभ्यास कर रहे हैं — बिना किसी आधुनिक टर्फ या महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। लेकिन यही कठोर अभ्यास उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है। वे सीख रहे हैं कि संसाधन मायने नहीं रखते, अगर जुनून और दिशा सही हो।

समापन- खेल से ही बनेगा भारत महान

जांजगीर-चांपा का यह हॉकी शिविर पूरे प्रदेश और देश के लिए उदाहरण है कि छोटे शहरों और सीमित साधनों में भी खेल की एक नई क्रांति की शुरुआत की जा सकती है। ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ी आज मुरुम के मैदान में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कल ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहरा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ हॉकी की नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष, और सफलता की भी है। हमें बस इतना करना है कि इन बच्चों को अवसर दें, मार्गदर्शन दें — और फिर देखिए, भारत की गली-गली से निकलेंगे अगली पीढ़ी के मेजर ध्यानचंद।

बढ़ती उम्र के साथ खानपान का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए अगर साठ के हो गए हैं तो इस तरह खानपान बेहतर कर सकते हैं

राखी श्रीवास्तव

आपका खानपान आपकी उम्र के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप साठ बरस के हैं तो आपके लिए क्या खाना अच्छा है और क्या नहीं, इस लेख में जानिए। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की ज़रूरतें भी बदलती हैं। ख़ासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद। मन मीठे और तले जैसे तरह-तरह के व्यंजनों की तरफ आकर्षित होता है। परंतु उम्र के इस पड़ाव में आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा दे, पाचन को सहज बनाए और दिनभर ऊर्जावान और हल्का महसूस कराए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने खानपान का ध्यान विशेष रूप से रखें। पौष्टिक खानपान शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ-साथ आपको मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान बनाए भी रखेगा।

तले-भुने खाने से दूरी ज़रूरी

60 की उम्र के बाद शरीर की पाचनशक्ति धीरे-धीरे कम होने लगती है। इस अवस्था में तले-भुने और भारी खाद्य पदार्थ, जैसे- समोसा, कचौरी, चकली, भुजिया आदि पचाना मुश्किल हो जाता है। यह भोजन सिर्फ़ पेट पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि गैस, एसिडिटी और थकान का कारण भी बनता है। जब शरीर में लगातार भारीपन रहता है तो नींद, मनोदशा और ऊर्जा का स्तर भी प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया है कि बुज़ुर्गों को हर बार चाय के साथ कुछ कुरकुरा या तला हुआ खाने की इच्छा होती है, लेकिन यह आदत धीरे-धीरे नुक़सानदेह बन सकती है।

बेहतर विकल्प... तेलयुक्त खाने की जगह भुने हुए मखाने, मूंग दाल चीला, ढोकला या जीरा-हींग से तड़की हुई हल्की सब्ज़ियां खा सकते हैं। ये ना सिर्फ़ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को हल्का और संतुलित भी रखते हैं।

मिठास और मैदे से करें परहेज़

उम्र के इस पड़ाव में मीठा और मैदे से बनी चीज़ें धीमा ज़हर साबित हो सकती हैं। बिस्किट, केक, मैदे के टोस्ट, मिल्क केक, हलवा या पेड़ा जैसी मिठाइयां देखने में तो लज़ीज़ लगती हैं, लेकिन इनमें पोषण नहीं होता। ये रक्त शर्करा को तेज़ी से बढ़ाती हैं, कब्ज़ को जन्म देती हैं और लंबे समय में मधुमेह, जोड़ों का दर्द और थकान की वजह बन सकती हैं। भोजन के बाद मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन अब ये आदत नुक़सानदेह हो सकती है। इस आदत को पूरी तरह ख़त्म किए बिना भी हम बेहतर विकल्प दे सकते हैं।

बेहतर विकल्प... मीठे के लिए गुड़-तिल से बने लड्डू, रागी लड्डू, 1-2 खजूर या भोजन के बाद आधा चम्मच गुलकंद ले सकते हैं। मैदे की जगह, मौसम के अनुसार मिलेट्स (जैसे- बाजरा, जौ आदि) की रोटी, सब्ज़ियों के साथ बेसन का टोस्ट और घी वाला पोहा भी बेहतर विकल्प हैं।

ठंडी और खट्टी चीज़ों से बचें

रोज़ भोजन में चटपटा अचार, ठंडी चीज़ें व पैक्ड ड्रिंक्स शामिल होना आम हो गया है। लेकिन यह आपके शरीर में जलन, उच्च रक्तचाप और वात जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। बाज़ार के तीखे और तेल से भरे हुए अचार में अत्यधिक सोडियम होता है, जिससे शरीर में पानी रुकता है और रक्तचाप असंतुलित हो सकता है। इसी तरह, फ्रिज से निकले काफ़ी देर पहले से कटा सलाद, ठंडी लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड जूस पाचन को बिगाड़ते हैं और शरीर में सूखापन, गैस और थकान पैदा करते हैं।

बेहतर विकल्प... इनके स्थान पर घर में बना नींबू या आंवले का कम तेल-मसाले वाला सादा अचार, पुदीना-धनिए की चटनी, जीरे वाली छाछ या गर्म सूप बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। गर्म सूप पिएं और भाप में पकी सब्ज़ियां खाएं। पेय में नींबू-पुदीना पानी या जीरा-धनिया का उबला पानी शरीर को ठंडक भी देगा और पाचन को भी मज़बूत बनाएगा।

निर्जन जगह बना लाखों का पुल, बिना इस्तेमाल हुआ जर्जर;
मरवाही में अफसर ठेकेदार का कारनामा...

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से सामने आया यह मामला छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना और बुनियादी ढांचा विकसित करना है, वहां पर जब भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें खुलने लगें, तो यह केवल धन की बर्बादी नहीं, जनविश्वास की हत्या भी मानी जाती है।

मरवाही विकासखंड के बदरोड़ी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव दैईगवा में मनरेगा मद से करोड़ों रुपए की लागत से तीन पुलियों का निर्माण कराया गया। यह गांव छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में आता है, जहां परिवहन सुविधा अत्यंत सीमित है और अनेक स्थानों पर जाने के लिए मार्ग भी नहीं हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन पुलियों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया गया है जहां इंसान तो दूर, मवेशी भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। चारों ओर जंगल और झाड़ियाँ हैं, कोई अप्रोच रोड नहीं है और आवाजाही का कोई साधन नहीं।

इस पूरे निर्माण कार्य की लागत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें प्रत्येक पुलिया पर करीब 19 लाख 50 हजार रुपए खर्च किए गए। यह आंकड़ा तब और चौंकाता है जब ग्रामीण बताते हैं कि ये पुलियाँ केवल दिखावे की हैं और इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। यहां तक कि लोगों ने जब पूछा गया कि वे इन पुलियों से होकर क्यों नहीं गुजरते, तो उनका सीधा जवाब था—मरना है क्या? यह टिप्पणी पुलियों की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है। घटिया सामग्री का उपयोग कर पुलियाँ बनाई गईं, जो बिना किसी उपयोग के ही जर्जर हो चुकी हैं। पुलिया की सतह पर हाथ फेरते ही सीमेंट का सूखा मसाला झड़ने लगता है। यह साफ संकेत है कि निर्माण में न केवल गुणवत्ता से समझौता किया गया, बल्कि निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों ने भी अपनी आंखें मूंद ली थीं।

दूसरी तरफ प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश जरूर दिए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने बताया कि जैसे ही मामला सामने आया, तत्काल जांच टीम गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि मटेरियल और मजदूरी के रेशियो में भारी अंतर है, जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निर्माण कार्य बिना प्लानिंग, सर्वे और उपयोगिता के किए जा रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से केवल फंड का दुरुपयोग किया गया है।

मनरेगा जैसी योजना, जो ग्रामीण भारत की रीढ़ मानी जाती है, उसका इस तरह से दोहन होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से गांवों में सड़क, पुलिया, तालाब, नाली जैसे कार्य कराए जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हो। लेकिन जब इस राशि का उपयोग निर्जन और

अप्रासंगिक स्थलों पर पुलिया बनाने में किया जाए, तो इससे न केवल शासन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि यह बताता है कि निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है।

स्थानीय लोगों की मानें तो उन्होंने कई बार इस तरह की अनियमितताओं की शिकायतें की थीं, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह शासन और प्रशासन के बीच संवादहीनता का उदाहरण है, जिसमें आम जनता की आवाज दबा दी जाती है।

यह भी देखने योग्य है कि इस पूरे मामले में एसडीओ और इंजीनियरों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। निर्माण कार्य उनकी देखरेख में हुआ और इसके बावजूद ऐसी गंभीर लापरवाहियाँ हुईं, जो दर्शाता है कि या तो वे जानबूझकर चुप रहे या फिर मिलीभगत का हिस्सा थे।

अब सवाल यह है कि क्या शासन दोषियों को वाकई सजा दिलवाएगा या यह मामला भी अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? क्या भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाएगी?

जनता के टैक्स से जमा हुए पैसे का इस तरह दुरुपयोग केवल आर्थिक अपराध नहीं है, यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी की भी उपेक्षा है। यदि शासन वाकई में सुशासन के दावे को मजबूत करना चाहता है, तो उसे इस मामले को उदाहरण बनाकर दोषियों को सख्त सजा दिलानी होगी और ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे भविष्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी की हिम्मत ना हो कि वह सरकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ करे।

इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान, उन्हें सजा दिलाना और सिस्टम में सुधार ही वह रास्ता है जिससे जनता का शासन में भरोसा दोबारा स्थापित किया जा सकता है। जब तक ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक सुशासन का दावा महज एक भाषण का हिस्सा ही रहेगा। (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

Chhattisgarh की जूही ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में बिखेरा जलवा, रैम्प वॉक से दिया खास मैसेज, ड्रेस पर टिकी नजरें...

इस साल का कान्स फिल्म फेस्टिवल दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा. फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने रेड कॉरपेट में रैम्प वॉक कर ग्लोबल वार्मिंग और इसके संरक्षण का संदेश दिया. ऐसा करने वाली जूही व्यास छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई।

इस साल का कान्स फिल्म फेस्टिवल दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा. फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने रेड कॉरपेट में रैम्प वॉक कर ग्लोबल वार्मिंग और इसके संरक्षण का संदेश दिया. ऐसा करने वाली जूही व्यास छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई ।

जूही का कान्स में जलवा

कान्स फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में इस बार ग्लैमर से हटकर एक गंभीर संदेश देखने को मिला. छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने रेड कारपेट पर जलती हुई पृथ्वी को दर्शाती ड्रेस पहनकर ग्लोबल वॉर्मिंग की ओर दुनिया का ध्यान खींचा. वियतनामी डिज़ाइनर नगुयेन टी ट्रीन द्वारा तैयार की गई यह ड्रेस तापमान वृद्धि और पर्यावरण असंतुलन का प्रतीक थी. जूही ने ग्रीनपीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लैनेट अभियान के तहत भारत का प्रतिनिधित्व किया।

ड्रेस से दिया ग्लोबल वॉर्मिंग का मैसेज

जूही ने कहा कि यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो चुपचाप जलवायु संकट झेल रहे हैं. एक मां होने के नाते, मुझे अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी की रक्षा करने की जिम्मेदारी और भी ज्यादा महसूस होती है. राष्ट्रीय निदेशक मोहिनी शर्मा के साथ उन्होंने समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक संकट और हाई सीस ट्रिटी जैसे मुद्दों को भी उठाया. एक छोटे से शहर से निकली यह आवाज आज भारत का नाम कान्स जैसे वैश्विक मंच पर गर्व से बुलंद कर रही है.

मिसेज इंडिया आईएनसी की फर्स्ट रनरअप रहीं

2022 में मिसेज इंडिया आईएनसी की फर्स्ट रनरअप बनीं. इसके बाद 2023 में कैलिफोर्निया में मिसेज ग्लोग पीपुल्स चॉइस का खिताब मिला. 2024 में चीन में मिसेज ग्लोब की जूरी में भारत से पहली प्रतिनिधि रहीं. और 2025 में पेरिस फैशन वीक में छह इंटरनेशनल डिजाइनर्स के लिए वॉक किया हैं।

एन. रघुरामन का कॉलम- काम का मतलब समर्पण है, 'चलता है' नहीं

इसी साल मार्च की बात है। एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी दूसरा व्यक्ति अंदर गया और उससे पांच हजार रुपए छीनकर भाग गया। पीड़ित ने उसका पीछा किया। 74 वर्षीय अनुराधा कुलकर्णी वहीं ट्रैफिक संभाल रही थीं और उन्होंने यह सब देखा।

उन्होंने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की, पीड़ित को लिफ्ट दी और चोर का पीछा करते हुए देखा कि वह टाटा कॉलोनी नामक एक रिहायशी इलाके में घुस रहा है। उनके तेज दिमाग को पता था कि कॉलोनी का केवल एक ही एग्जिट पॉइंट है, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचित कर गेट पर पीड़ित के साथ इंतजार किया।

एक घंटे बाद, आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पैसे बरामद कर लिए। दो महीने पहले एक व्यक्ति सड़क पार करते समय ट्रक से कुचलकर मारा गया। सड़क के बीचों-बीच खड़ी हुई अनुराधा ने देखा कि पीड़ित की चप्पल डिवाइडर में फंस गई थी, जिससे वह चलते ट्रक के सामने गिर गया था।

गुस्साए स्थानीय लोग ट्रक ड्राइवर पर हमला करने लगे। अनुराधा ने तुरंत एक्शन लिया और गवाही दी कि यह ड्राइवर की गलती नहीं थी। वह इस चल रहे मामले में मुख्य गवाह हैं। लगभग छह महीने पहले एक सोसाइटी के चौकीदार का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस ने अनुराधा से आरोपी की पहचान करने में मदद मांगी।

उन्होंने तीन दिनों में मोबाइल चुराने वाले सफाईकर्मी की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि यह 74 वर्षीय महिला हमेशा सड़क के बीच में क्या करती रहती हैं? हर दिन वह बाइक पर घूमती हैं, जहां भी ट्रैफिक नजर आता है, वहां उतरकर ट्रैफिक संभालती हैं, एंबुलेंस को तेजी से जाने में मदद करती हैं और स्कूली बच्चों को सड़क पार कराती हैं।

लगभग 30 साल पहले की बात है, एक बार उन्होंने देखा कि मुंबई में सांताक्रूज में एक स्कूल के पास लोग गलत लेन में आ रहे थे, तभी उन्होंने अकेले ही लोगों को वहां से आने से रोक दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें ऐसा करते देखा और उन्हें ट्रैफिक वार्डन के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने मुंबई के बायकला में ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग के बाद लिखित और मौखिक परीक्षा पास की। तब से, वह मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाके जुहू-विले पार्ले-सांताक्रूज में स्वेच्छा से यह काम कर रही हैं। उनके एक फोन कॉल पर पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है क्योंकि वह केवल तभी कॉल करती हैं जब वह स्थिति को संभाल नहीं पातीं, चाहे वह ट्रैफिक की समस्या हो या कोई असामाजिक गतिविधि।

साल 2014 में बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने उनके उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें सम्मानित किया था और उन्होंने कोविड के दौरान कोरोना पॉजिटिव लोगों को भोजन पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इन उपनगरों में सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम होने पर किसी को उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद पहुंच जाती हैं और ट्रैफिक वार्डन का काम करती हैं।

ट्रैफिक सुचारू होने के बाद, वह अपनी बाइक लेती हैं और अगले

स्थान पर चली जाती हैं, जहां उनकी जरूरत होती है। ठेले वाले से लेकर दुकानदार तक, वहां के सभी लोकल लोग इस शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है।

बैंक में काम करने वाले उनके पति का बहुत पहले निधन हो चुका है और उनकी सास ने उन्हें एक घर दिया है, जिसके किराए से और समय-समय पर रिश्तेदारों की मदद से उनकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। इसलिए वह मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए फ्री में काम करते हुए अपना सारा समय बिताती हैं।

फंडा यह है कि जो लोग किसी भी काम के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, फिर चाहे वह स्वप्रेरणा से हो या उसके एवज में कोई पैसा मिले, ऐसे लोगों को हमेशा पहचान और सराहना मिलती है। इसलिए कहीं भी काम करें, काम के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को सबसे ऊपर रखें क्योंकि इससे आपको पैसा मिलता है या प्रशंसा और ज्यादातर मामलों में तो दोनों।

श्रमिकों की मेहनत का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान...

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, एक मई, एक ऐसा दिन है जो श्रम की महत्ता, मेहनतकश हाथों के सम्मान और सामाजिक न्याय की भावना को उजागर करता है। यह दिवस न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि 1886 के शिकागो आंदोलन को भी याद दिलाता है, जिसमें मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे आत्म विकास के अधिकार की मांग की थी, बल्कि यह आज भी उस संघर्ष को व्यक्त करता है जो श्रमिक अपने अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के लिए हर दिन करते हैं।

एमसीबी जिले में श्रमिक कल्याण योजनाओं का दिख रहा प्रभाव

छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला जो छत्तीसगढ़ के नए जिलों में से एक है, यहाँ के मेहनतकश श्रमिकों की मेहनत और लगन इस क्षेत्र की आर्थिक धड़कन बन चुकी है। इस जिले की सड़कों से लेकर निर्माण स्थलों तक, खेतों से लेकर खदानों तक श्रमिकों का पसीना इस इलाके की तरक्की में संजीवनी की तरह काम करता है। जब हम इस क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जिला श्रमिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। मंडल स्तर पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत 30,534 श्रमिक पंजीकृत हैं और असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल में 30,118 श्रमिकों का नाम दर्ज है। जिला गठन के बाद भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में 6,257 और असंगठित क्षेत्र में 4,601 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। कुल मिलाकर 71,510 श्रमिकों का पंजीकरण होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँच रही हैं और श्रमिक अपने हक के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

ब्लॉक स्तर पर बात करें तो मनेंद्रगढ़ में 26,065 श्रमिक पंजीकृत हैं, वहीं खड़गवां ब्लाक में 22,847 और भरतपुर ब्लाक में 10,739 श्रमिक पंजीकृत है, ये आँकड़े न केवल प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाते हैं बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी कितनी अहम है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं है लागू

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाएं श्रम की गरिमा को बढ़ावा देने और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सराहनीय पहल हैं। महतारी जतन योजना के तहत अब तक 1,351 श्रमिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। यह योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण और प्रसवपूर्व देखभाल हेतु वित्तीय सहायता देती है, ताकि मातृत्व और शिशु जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत 2,672 विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की गई है, जिससे उन्हें स्कूल जाने में सुविधा हो और शिक्षा बाधित न हो। मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत

1,887 श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप औजार उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर कार्य में दक्षता ला सकें। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 306 महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन दी गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। वहीं श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, जिसके तहत 3,536 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। इससे शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है और भविष्य की राहें खुली हैं।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना में 211 छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास योजना में 1,031 श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें नई तकनीकों और कार्य दक्षता की जानकारी दी गई है, जिससे वे बेहतर रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकें। सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत 1,230 निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज़ आदि दिए गए, जिससे उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 78 श्रमिक परिवारों को राहत दी गई, जिनके सदस्य या तो दिव्यांग हुए या जिनकी मृत्यु कार्य के दौरान हो गई हो ।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 494 लड़कियों को विवाह, शिक्षा या स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी गई। वृद्ध श्रमिकों को भी सरकार ने नहीं भुलाया, उन्हें मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत पेंशन स्वरूप 56 लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है । इसके अतिरिक्त बच्चों को नि:शुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना से 507 छात्र लाभान्वित हुए, जिससे वे गरिमामय तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे श्रमिक बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना के अंतर्गत 8 छात्रों को संसाधन व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। निर्माण श्रमिकों को आवास हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 7 श्रमिकों को घर बनाने में मदद मिली है ।

केंद्र सरकार की श्रमिक कल्याण योजना से भी हो रहे है लाभान्वित

केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 709 श्रमिकों को नाममात्र प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,412 श्रमिकों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिला है, जिसमें आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की एक और उल्लेखनीय पहल है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना जिसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 को मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद परिसर में किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 200 से 250 श्रमिकों को मात्र 05 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह न केवल भूख की समस्या का समाधान है, बल्कि यह श्रमिकों को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने की राह भी देता है।

छत्तीसगढ़ सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हम सभी का कर्तव्य बनता है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें सम्मान दें और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहभागी बनें। क्योंकि जब श्रमिक मुस्कुराता है, तो समाज मुस्कुराता है। जब श्रमिक सुरक्षित होता है, तो राष्ट्र सशक्त होता है। और जब श्रमिक प्रगति करता है, तो देश आगे बढ़ता है।

बकरी पालन बना आर्थिक सशक्तिकरण का आधार...

किसानों को मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गरीब किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से बकरी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रशासन ने अभिनव पहल की है। अब जिले में जल्द ही अफ्रीकन नस्ल 'बोयर' के बकरा-बकरी नजर आएंगे, जिनका वजन स्थानीय नस्ल की तुलना में तीन से चार गुना अधिक होगा है। इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम मिलेगा। बकरी पालन आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे किसानों के लिए 'एटीएम' की तरह कार्य करता है। इसे पालना आसान होता है और जरूरत पड़ने पर बेचकर तत्काल नकद आय अर्जित की जा सकती है। स्थानीय नस्ल के बकरों का अधिकतम वजन 20 से 25 किलोग्राम तक होता है, लेकिन अब कृत्रिम गर्भाधान से अफ्रीकन बोयर जैसे भारी भरकम नस्ल के बकरा-बकरी पालने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिनका वजन 80 से 100 किलो तक होता है।

प्रशासन की नवाचार पहल से मिलेगी आर्थिक मजबूती

कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर पशुपालन विभाग द्वारा 7800 सीमेन डोज मंगवाए गए हैं, जिनमें भारतीय नस्ल जमुनापारी, सिरोही, बारबरी के साथ पहली बार अफ्रीकन बोयर नस्ल के सीमेन भी शामिल हैं। ये सीमेन उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ऋषिकेश के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में जिला पशु रोगी कल्याण समिति से भी आर्थिक सहयोग मिला है।

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. सी.के. मिश्रा ने बताया कि, यह पहली बार है जब अफ्रीकन बोयर नस्ल का सीमेन सरगुजा में उपलब्ध कराया गया है। सफेद रंग की इस नस्ल का गला और सिंग तक का भाग कत्थई रंग का होता है। वजन अधिक होने के कारण बकरी पालन से ग्रामीणों को लाभ भी अधिक मिलेगा।

सफल नवाचार का सरगुजा जिले के हर ब्लॉक में होगा विस्तार

छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले सूरजपुर और सरगुजा जिले में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई थी। अब इस नवाचार को मिली सफलता के बाद सरगुजा जिले के सभी विकासखंडों में इसे लागू कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को बेहतर नस्ल की बकरी पालने और उससे अधिक आय प्राप्त होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बकरी पालन से किसान अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम

यह पहल न केवल ग्रामीणों को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगे, जिससे बकरी पालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से अब बकरी पालन सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि समृद्धि का जरिया बनता जा रहा 7 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

ब्राम्हण समाज ने किया है ज्ञान और संस्कार देने का कार्य- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डंगनिया में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ब्राम्हण समाज ने सदैव समाज को ज्ञान और संस्कार देने का कार्य किया है। उन्होंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है और प्रभु श्रीराम हमारे भाँचा हैं। रामलला मंदिर निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गौरव और आस्था का विषय है। 'श्रीरामलला दर्शन योजना' के अंतर्गत अब तक 22,000 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें श्रद्धालु सरकारी व्यय पर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कराने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास के लिए एक सशक्त 'विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया है और नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के '2047 तक विकसित भारत' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम 'विकसित छत्तीसगढ़' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में ब्राम्हण समाज की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के अल्पकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने की बात हो या किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिलाना—हमने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। बस्तर और सरगुजा में जनजातीय समाज के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रक्रियाओं, संस्थाओं और क्रियाओं के शुद्धिकरण का कार्य जारी है। राज्य निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कौशल उन्नयन, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएससी में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है, और कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज एक प्रगतिशील समाज है, जिसने हमेशा विमर्श और विचारों का स्वागत किया है।

इस अवसर पर महंत श्री वेदप्रकाशाचार्य, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री सुशांत शुक्ला, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, श्रीमती सुमन अशोक पांडेय, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राम्हण समाज अध्यक्ष श्री शिवांजल शिव गोविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पोषक तत्वों से भरपूर भिंडी, गर्मी के लिए है बेस्ट...

जी वी एस रूक्मणी देवी

हरी और लंबी-लंबी सब्जी जिसे 'लेडीज फिंगर' या भिंडी और कई जगह ओकरा भी कहते हैं न केवल स्वाद में बेहतरीन बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। भिंडी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर के साथ विटामिन 'ए', 'सी' के साथ 'पोटेशियम' और 'मैग्नीशियम' जैसे खनिज तत्व के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। सुपाच्य और ठंडी तासीर की वजह से यह गर्मी के मौसम के लिए बेहतरीन सब्जियों की लिस्ट में शामिल है।

गर्मियों में भिंडी बाजार में आसानी से मिल जाती है, इसलिए इस सीजन में लोग भिंडी का सेवन करते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही सुपाच्य भी होती है। स्वाद से भरपूर भिंडी खाने से कई फायदे भी मिलते हैं।

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन (2021) में इसकी महत्ता बताई गई है। स्टडी के अनुसार, ओकरा की उत्पत्ति इथियोपिया के पास हुई थी, जहां 12वीं शताब्दी के दौरान मिस्र में इसे उगाया जाता था और उसके बाद पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इसकी खेती होने लगी। ओकरा को ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है और यह एक लोकप्रिय फसल है। यह व्यापक रूप से उगाई जाने वाली खाद्य फसल है और विश्व स्तर पर अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। भिंडी की हरी फली की आमतौर पर सब्जी बनाई जाती है, जबकि फली का अर्क सूप के साथ-साथ सॉस के कई व्यंजनों में उनकी चिपचिपाहट बढ़ाने के लिए या फिर गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में भी काम करता है। भिंडी के फल का एक और उल्लेखनीय प्रयोग अचार उद्योग में किया जाता है।

भिंडी के सेवन से पाचनतंत्र मजबूत होता है और यह कई समस्याओं को दूर करने के साथ सेहत भी दुरुस्त रहती है। इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम के साथ ही कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर भिंडी की तासीर ठंडी होती है। भिंडी में प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, फाइबर के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट समेत अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। भिंडी का पानी पीने से यह आपके पेट को ठंडा रखता है।

भिंडी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पाचनतंत्र को मजबूत करने के साथ पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं को भी दूर करती है। कब्ज, वात, कच्ची डकार में राहत मिलती है। पेट के साथ ही भिंडी हृदय के लिए भी फायदेमंद है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर होने के साथ ही हार्ट की सेहत दुरुस्त रहती है। यदि आपको मधुमेह की शिकायत है, तो भिंडी का सेवन जरूर करें। इसमें ग्लाइसेमिक नाम का तत्व पाया जाता है, जिसके सेवन से मधुमेह नियंत्रित होता है। भिंडी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है।

'वॉर 2' से मचेगा धमाका- 5 देश, 150 दिन की शूटिंग और 6 बड़े एक्शन धमाके...

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर यह फिल्म यशराज स्पाई यूनिवर्स का अगला बड़ा अध्याय है, जिसकी भव्यता, एक्शन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति ने पहले ही दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता जगा दी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 'वॉर 2' की शूटिंग का कार्य लगभग 150 दिनों तक चला है और इसे भारत सहित पांच अन्य देशों–स्पेन, इटली, जापान, अबू धाबी और रूस–में अंजाम दिया गया है। खासतौर पर जापान और रूस में फिल्माए गए दृश्यों को लेकर निर्माताओं का दावा है कि वे फिल्म की इंटरनेशनल अपील को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

हर एक्शन सीक्वेंस को दी गई अलग पहचान

फिल्म में 6 भव्य एक्शन सीक्वेंस शामिल किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग थीम और स्टाइल में शूट किया गया है। इन दृश्यों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित स्टंट कोरियोग्राफर्स की सेवाएं ली गई हैं, जिन्होंने इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय एक्शन फिल्मों में काम किया है।

बताया जा रहा है कि एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए उन्नत तकनीक, हाई–टेक गजेट्स और वास्तविक लोकेशन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

ऋतिक बनाम एनटीआर- जबरदस्त टक्कर

'वॉर 2' में ऋतिक रोशन एक बार फिर अपने लोकप्रिय किरदार कबीर के रूप में लौट रहे हैं। वहीं, फिल्म में पहली बार शामिल हो रहे तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जिसे ग्रे शेड्स के साथ प्रस्तुत किया गया है। दोनों सितारों के बीच फिल्म में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, जिसकी झलक पहले से ही रिलीज हुए टीज़र में नजर आ चुकी है। फैंस इस मुकाबले को लेकर बेहद रोमांचित हैं।

निर्देशन संभाल रहे हैं अयान मुखर्जी

फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। अयान इस बार एक्शन और इमोशन को संतुलित रूप से परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिल्म को केवल एक मसाला एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टाइल सिनेमा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

यशराज स्पाई यूनिवर्स का विस्तार

'वॉर 2' यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित स्पाई यूनिवर्स की चौथी कड़ी है। इससे पहले इसी यूनिवर्स में सलमान खान की टाइगर सीरीज़, शाहरुख खान की पठान और ऋतिक की वॉर रिलीज़ हो चुकी हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस फिल्म में स्पाई यूनिवर्स के अन्य प्रमुख किरदारों के कैमियो की संभावना भी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है।

तीन भाषाओं में होगी रिलीज

'वॉर 2' को 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगू में एक साथ रिलीज किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड को ध्यान में रखते हुए रिलीज की जा रही इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की उम्मीद जताई जा रही है।

टीज़र ने बढ़ाई उम्मीदें

फिल्म का टीज़र हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर की झलक, भव्य लोकेशंस, प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर और अत्याधुनिक एक्शन सीक्वेंस ने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ा दिया है। भव्य बजट, बेहतरीन स्टारकास्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग और यशराज की मजबूत प्रोडक्शन वैल्यू के साथ 'वॉर 2' इस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सिनेमा के इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकती है। दर्शकों को अब 14 अगस्त का बेसब्री से इंतज़ार है, जब यह बहुप्रतीक्षित फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।

आपरेशन सिन्दूर क्या है...

ऑपरेशन सिन्दूर भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कूटनाम है। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों ने नागरिक क्षेत्रों (मस्जिदों सहित) को निशाना बनाया और एक बच्चे सहित 26 पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला,किंतु ये दावा झूठा निकला।जांच में पता चला कि आतंकवादी मस्जिद की आड़ में आतंकी साजिशें करते थे। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज़ शरीफ़ ने हमलों को युद्ध की कार्रवाई कहा और जवाब देने का सौगन्ध लिया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी तोपख़ाने ने तीन भारतीय नागरिकों को मार डाला।

भारतीय हमले भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम नरसंहार की प्रतिक्रिया में किए गए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी %प्रतिरोध मोर्चा% नामक आतंकवादी संगठन द्वारा ली गयी थी। मारे गए लोग हिन्दू पर्यटक थे, जिनमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना भी देखा गया, जिन पुरुषों का खतना नहीं था,उन्हें उनके परिवार के सामने हिन्दू होने कारण मार दिया गया।भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप लगाया, हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया। किन्तु रिपोर्ट्स के मुताबिक,आतंकवादियों में शामिल एक आतंकवादी हाशिम मूसा,पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्सेज में एक भूतपूर्व पैरा कमांडो रहा है,जो पाकिस्तान की संलिप्तता को दर्शाता है।हमले ने 2025 के भारत-पाकिस्तान गतिरोध को जन्म दिया, जो व्यापक कश्मीर संघर्ष का हिस्सा है।

कश्मीर विवाद, जो 1947 से जारी है, ने इस विवादित क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और झड़पों को बढ़ावा दिया है।

22 अप्रैल 2025 को, भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में एक हमले में 26 नागरिक मारे गए और इसकी ज़िम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन, प्रतिरोध मोर्चा ने ली। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका पाकिस्तान खण्डन करता है। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानियों के लिए वीजा निलम्बित कर दिया और सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया। दोनों देशों ने सैन्य मुद्रा दिखाई, पाकिस्तान ने 3 मई को बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और भारत ने सैन्य अभ्यास किया।

इस अभियान को सिन्दूर कोड नाम दिया गया था, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पहलगाम हमले में हिन्दू पुरुषों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था, उनकी पत्नियों को बख़्श दिया गया था।

6 मई 2025 को, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर (मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली) और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत (बहावलपुर) में छह स्थानों को लक्षित करते हुए चौबीस हमले किए गए, यानी नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के पार।

भारत सरकार ने इन हमलों को केन्द्रित, सन्तुलित और ग़ैर-विस्तारवादी बताया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतङ्कवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, और किसी भी

पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को नहीं मारा गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, और हमलों में बच्चे मारे गए। भारतीय हमलों से प्रभावित स्थानों में से एक मुज़फ़्फ़राबाद की बिलाल मस्जिद थी, जहाँ रॉयटर्स ने क्षति की सूचना दी। पाकिस्तान के रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने शुरू में कहा कि भारतीय सैनिकों को बन्दी बना लिया गया है और विमानों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने बाद में स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को बन्दी नहीं बनाया गया था। भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की सुबह 23 मिनट के ऑपरेशन सिन्दूर में SCALP मिसाइलों और स्क्रू हैमर बमों से लैस राफेल विमानों को तैनात किया।

एक पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि हमले भारतीय विमानों द्वारा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना किए गए। हमलों से मुजफ्फराबाद में विस्फोट और बिजली गुल हो गई। पाकिस्तानी प्रांत पंजाब की मुख्यमन्त्री मरयम नवाज़ ने निवासियों से घरों के अन्दर रहने का आग्रह किया। श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने ऊपर भारी लड़ाकू विमानों की गतिविधि की सूचना दी। भारतीय सेना ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखा जिसमें #PahalgamTerrorAttack (अनुवाद-पहलगाम आतङ्कवादी हमला) हैशटैग सहित Justice is Served! (अनुवाद- न्याय हुआ!) लिखा। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक गाँव भीमबर गली में गोलीबारी की।

जैश-ए-मोहम्मद के अनुसार, बहावलपुर में एक भारतीय हवाई हमले में नेता मसूद अज़हर के परिवार के दस सदस्यों के अलावा चार करीबी सहयोगी मारे गए।

7 मई 2025 को, पाकिस्तान ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में जम्मू और कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान वायुसेना ने पाँच या दो भारतीय विमानों को मार गिराया। सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय नष्ट हो गया।

भारतीय मीडिया ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी जेएफ-17 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय मार गिराया गया। विमान भारत के पुलवामा के पंपोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के भारतीय प्रेस परिषद् ने दावा किया कि कोई भी भारतीय जेट विमान नहीं गिराया गया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त मिग-29 को दिखाने वाली तस्वीरें कथित तौर पर एक साल पुरानी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि न तो भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय और न ही श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया गया था।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा कि भारतीय हमलों में कम से कम दो बच्चों सहित 26 नागरिक मारे गए और कम से कम 35 अन्य घायल हो गए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, भारत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अन्दर तोपख़ाने की गोलाबारी में तीन नागरिक मारे गए।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अनुसार, सेना द्वारा भारतीय वायुसेना के पाँच लड़ाकू जेट और एक ड्रोन मार गिराया गया। द गार्डियन ने ख़बर दी कि श्रीनगर के पास, जम्मू और कश्मीर के अंदर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

परिणाम

कराची और लाहौर में हवाई क्षेत्र 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। पंजाब में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जबकि परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं।

स्पाइस जेट, इंडिगो और एअर इंडिया ने इस क्षेत्र में उड़ानें रोक दीं, जबकि एयर फ्रांस और लुफ़्थान्सा ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज़ किया। तुर्की एयरलाइंस, जज़ीरा एयरवेज़ और कुवैत एयरवेज़ द्वारा संचालित ढाका जाने वाली तीन अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को मस्क़त, दुबई और कुवैत नगर की ओर मोड़ दिया गया। मलेशिया एयरलाइंस और बाटिक एयर ने दोनों देशों के शहरों के लिए संचालन निलम्बित कर दिया और/या उड़ानों का मार्ग बदल दिया।

गर्मी में बच्चों में बढ़ता डायरिया- डॉक्टर से जानें बचाव के 7 तरीके...

मई का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है। हर बीतते दिन के साथ तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू के कारण छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन, डायरिया, उल्टी-दस्त और बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। अस्पतालों में इन समस्याओं से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी इजाफा होने लगता है। यह स्थिति खासकर कमजोर और कुपोषित बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अगर डायरिया या डिहाइड्रेशन के लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि गर्मी के इस मौसम में बच्चों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाए और किसी भी लक्षण को हल्के में न लिया जाए।

(लेखक- संदीप सिंग)

तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि गर्मी में बच्चों को किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? साथ ही जानेंगे कि-

डायरिया बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? इसके खतरे से कैसे बचा जा सकता है?

सवाल- डायरिया क्या है?

जवाब- यह एक पेट की बीमारी है, जिसमें बार-बार पतला या पानी जैसा दस्त (मल) होने लगता है। यह तब होता है, जब पेट सही से खाना नहीं पचा पाता या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। डायरिया में शरीर से पानी और नमक (सोडियम) तेजी से निकल जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और डिहाइड्रेट हो सकता है।

सवाल- हर साल डायरिया से कितने बच्चों की मौत होती है?

जवाब- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, डायरिया से हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 4.43 लाख और 5-9 वर्ष की उम्र के लगभग 50 हजार से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। इसलिए इसके लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नीचे दिए ग्राफिक में डायरिया के लक्षण देख सकते हैं।

सवाल- बच्चों में डायरिया का खतरा ज्यादा क्यों होता है?

जवाब- बच्चों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अक्सर बच्चे बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं या गंदे खिलौने और अन्य सामान मुंह में डाल लेते हैं। इससे बैक्टीरिया और वायरस उनके पेट में चले जाते हैं, जिससे डायरिया हो सकता है। गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन फैलने का खतरा और बढ़ जाता है, इसलिए यह समस्या आम हो जाती है। इसके मुख्य कारण ग्राफिक से समझिए-

सवाल- गर्मी में नवजात शिशुओं की देखभाल में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

जवाब- डॉ. अंशु शर्मा बताती हैं कि नवजात शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है। तापमान में हल्का-सा बदलाव भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी देखभाल में बेहद सावधानी की जरूरत होती है। इसलिए नीचे दी गई कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।

केवल मां का दूध पिलाएं

6 महीने तक के शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। यही उसका खाना, पानी और दवा है।

शिशु के लिए चुनें हवादार कमरा

जन्म से करीब 6 महीने तक उसे सीधी धूप, गर्म कमरे या भीड़भाड़ वाली जगहों पर न ले जाएं। एसी या कूलर की हवा सीधे न लगने दें, लेकिन कमरे को ठंडा रखें।

हल्के और सूती कपड़े पहनाएं

बच्चे को ढीले, हल्के रंग के कॉटन कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे के कपड़े बार-बार कपड़े गीले हों तो उन्हें तुरंत बदलें।

डायपर की सफाई और चेकिंग

गर्मी में रैशेज का खतरा बढ़ता है, इसलिए डायपर समय पर बदलें और स्किन को सूखा रखें।

नहलाने में सावधानी

रोज हल्के गुनगुने या सामान्य ताजे पानी से नहलाएं। नहलाने के तुरंत बाद शरीर को सुखाकर कपड़े पहनाएं।

साफ-सफाई का खास ध्यान रखें

नवजात को गोद लेने से पहले हाथ जरूर धोएं। साथ ही बच्चे के आसपास साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें।

बुखार, सुस्ती या रोने पर डॉक्टर से संपर्क करें

अगर न्यू बोर्न बेबी को पसीना ज्यादा आ रहा हो, वह दूध नहीं पी रहा हो, सुस्त हो या लगातार रो रहा हो तो ये डिहाइड्रेशन या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सवाल- भीषण गर्मी में बच्चों के खान-पान और हाइड्रेशन को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

जवाब- गर्मी में बच्चे बहुत जल्दी थकते हैं, उन्हें पसीना ज्यादा आता है और शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है। ऐसे में उनका खान-पान और पानी पीने की आदत पर खास ध्यान देना जरूरी है। उसे छाछ, गन्ने का जूस, नारियल पानी जैसे हेल्दी ड्रिंक्स भी दे सकते हैं।

हल्का और ताजा खाना दें

बच्चों को गर्मियों में ऐसा खाना दें, जो आसानी से पच जाए। जैसे दाल-चावल, रोटी-सब्जी, खिचड़ी। बासी या बाहर का खाना बिल्कुल न दें।

ताजे फल खिलाएं

तरबूज, खरबूजा, पपीता, आम, खीरा, ककड़ी जैसे फल बच्चों के शरीर को ठंडक देते हैं। साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं।

ज्यादा मसालेदार या तला-भुना खाना न दें

बच्चों को तीखा, ज्यादा तला-भुना या तेल वाला खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे पेट खराब हो सकता है।

हमेशा बच्चों की बोतल भरकर रखें

अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसे साफ पानी की बोतल दें। उसे ये भी बताएं कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना कितना जरूरी है।

सवाल- किस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

जवाब- अगर डायरिया के लक्षण दो दिन से ज्यादा दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर मल में खून दिखे, तेज बुखार हो, बार-बार उल्टी हो या बच्चा बहुत सुस्त लगे तो यह भी खतरे के संकेत हो सकते हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर शरीर वाले लोगों में डायरिया जल्दी गंभीर हो सकता है। इसलिए उनके मामले में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मोटापे की समस्या से परेशान हैं, आज से ही पानी को दिनचर्या में करें शामिल....

हमारे देश में बहुत से लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं। कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं। अगर आप भी मोटापा कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। गर्मी के दिनों में हम सभी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीते हैं। अक्सर लोग गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीते हैं। ठंडे पानी को लेकर हमारे समाज में एक आम धारणा है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा।

बता दें कि वास्तविकता इसके विपरीत है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं, तो शरीर को उस पानी को अपने सामान्य तापमान तक गर्म करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा (कैलोरी) खर्च करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया वास्तव में आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर देती है।

'द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म' में 2003 में प्रकाशित हुई एक स्टडी (अध्ययन) के अनुसार, 500 मिली ठंडा पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट 30त्न तक बढ़ सकता है, जो एक घंटे से अधिक समय तक रहता है। यह छोटा-सा प्रभाव नियमित रूप से दोहराने पर कैलोरी बर्न को बढ़ाता है, जो वजन नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकता है।

ठंडा पानी और थर्मोजेनेसिस का विज्ञान

जब आप ठंडा पानी पीते हैं, तो यह शरीर के आंतरिक तापमान को थोड़ा कम कर देता है। शरीर इसे सामान्य तापमान (लगभग 37एष्ट) पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है। इस प्रक्रिया को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें शरीर गर्मी पैदा करने के लिए कैलोरी बर्न करता है।

वजन कम करने में ठंडे पानी के फायदे

ठंडा पानी पीना वजन घटाने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। ठंडा पानी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है। भोजन से पहले एक गिलास ठंडा पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप कम खाते हैं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है, जो पाचन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

पानी पीने का सही तरीका

सुबह 1-2 गिलास ठंडा पानी पिएं। आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, ये पेय किडनी से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करते हैं। खाने से 20-30 मिनट पहले 500 मिली ठंडा पानी पिएं, ताकि भूख नियंत्रित हो। छोटे-छोटे घूंटों में 2.5-3 लीटर पानी पिएं।

सावधानियां

बहुत अधिक ठंडा पानी न पिएं, क्योंकि यह पाचन को प्रभावित कर सकता है।

किडनी या हृदय रोगियों को ठंडा पानी पीने और पानी की मात्रा के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर ठंडे पानी से एलर्जी हो, तो सामान्य तापमान का पानी चुनें।

वायनाड- हरी-भरी वादियों की बीच सुकूनभरी सैरगाह...

वायनाड पश्चिमी घाटों में केरल में स्थित हरियाली से घिरा एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यहां वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के अलावा कॉफी और चाय के बागान, झीलें, प्राचीन गुफाएं आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह हर मौसम में घूमने के लिए एक आदर्श स्थल है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जंगल सफारी पर जाना एक विशेष अनुभव होता है। यहां मुथंगा और थोलपेट्टी दो जगहों से जंगल सफारी उपलब्ध हैं। ये दोनों क्षेत्र हरियाली और अनूठी जैव विविधता से भरपूर हैं। वायनाड में हाथियों के दर्शन आम बात है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बाघ भी देखने को मिल जाएंगे। थोलपेट्टी का क्षेत्र नागरहोल टाइगर रिजर्व के करीब है, इसलिए यदि आप थोलपेट्टी के पास रुकते हैं तो नागरहोल भी घूमने का अवसर मिल सकता है। मुथंगा की ओर जाने वाली सड़क पर ही हाथियों के दर्शन हो सकते हैं। स्थानीय लोग सलाह देते हैं कि यदि हाथी दिख जाए तो वाहन से बाहर न निकलें। यह घातक हो सकता है।

कॉफी और चाय बागानों की सफारी वायनाड के आस-पास चाय और कॉफी बागानों के लिए भी जीप सफारी उपलब्ध है। लगभग हर होटल इस तरह की सफारियां अरैंज करवाता है। हरे-भरे बागानों के बीच से गुजरना एक बेहद शानदार अनुभव होता है। इन बागानों की ऊंची-नीची सड़कों से पश्चिमी घाट का मनोहारी दृश्य दिखता है। बागानों के भीतर आप चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं। यहां आपको कई प्रकार के फूल और पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ होटल और होमस्टे तो इन्हीं बागानों के भीतर स्थित हैं, जहां ठहरना वास्तव में प्रकृति की गोद में रहने जैसा अनुभव देता है।

चेम्ब्रा पीक के हार्ट लेक तक ट्रेक चेम्ब्रा पीक वायनाड का सबसे ऊंचा स्थल है। उसकी चोटी पर दिल के आकार की एक झील स्थित है। यह एक आसान ट्रेक माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। लेकिन आसान ट्रेक भी कुछ मेहनत तो मांगते ही हैं। हरे-भरे रास्ते पर चढ़ाई के बाद जब आपको उस दिल-आकार की झील की एक झलक नजर आती है तो उससे आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। हालांकि यह ट्रेकिंग मुफ्त नहीं है। यहां ट्रेकिंग के लिए प्रवेश शुल्क और कैमरा शुल्क लिया जाता है। हालांकि कभी-कभी यहां अचानक से कोहरा छा जाता है, जिससे आसपास के नजारे पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई देते। फिर भी यह ट्रेक शानदार अनुभव देता है। लेकिन घनघोर बारिश (15 जून से सितंबर अंत तक) के मौसम में यहां जाने से बचना चाहिए।

एडक्कल गुफाएं एडक्कल की गुफाएं दरअसल प्राचीन काल के रॉक शेल्टर्स हैं। ये अंबुकुट्टी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित हैं, जो वायनाड से करीब 25 किलोमीटर दूर हैं। ये लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित

है और इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इन गुफाओं की खोज 1895 में फ्रेड फॉसेट ने की थी। इन रॉक शेल्टर्स की दीवारों पर कई चित्र बने हुए हैं। चट्टानों पर बने चित्रों में इंसानी तस्वीरों के अलावा कई चीजें दर्शाई गई हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ सबसे पुराने चित्र 6,000 ईसा पूर्व के हैं।

15 जून तक जा सकते हैं वायनाड

कब जाएं? घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई अंत का होता है। जून में यहां बारिश शुरू हो जाती है। फिर भी 15 जून तक जा सकते हैं। बारिश में हालांकि बहुत हरियाली होती है और झरने पूरे यौवन पर होते हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण ट्रेकिंग और सफारी में दिक्कत हो सकती है।

कैसे जाएं? वायनाड केरल के एक प्रमुख शहर कोझिकोड के काफी करीब है, जहां से हर तरह के आवागमन की सुविधा मिल जाती हैं। कोझिकोड हवाई अड्डा वायनाड से 86 किलोमीटर दूर स्थित है। रेलवे स्टेशन भी कोझिकोड में ही है। यह सड़क मार्ग से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई शहरों से जुड़ा है।

कहां ठहरें ? हाई रेंज में यहां चाय-काफी के बागानों में कई रिजॉर्ट बने हुए हैं। लेकिन मिड रेंज भी ठहरने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी परियोजना को मिला बॉलीवुड का समर्थन

अभिनेता हर्मन बावेजा ने जताई गहरी रुचि, रायपुर में किया औपचारिक एलान...

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता हर्मन बावेजा ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फिल्म सिटी परियोजना के साथ जुड़ने की इच्छा जताते हुए इसे निवेश से कहीं अधिक, एक रचनात्मक और सांस्कृतिक साझेदारी करार दिया। यह फिल्म सिटी नवा रायपुर अटल नगर में 100 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है और इसे आगामी वर्षों में देश की सबसे आधुनिक और संस्कृति-संवेदनशील फिल्म सिटी के रूप में उभारा जाना है।

प्रेस वार्ता से पूर्व बावेजा ने अटल नगर में प्रस्तावित फिल्म सिटी स्थल का निरीक्षण किया और इसके भूगोल, अधोसंरचना और विस्तार योजनाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे संतुलित और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी नीति बताया। यह नीति न केवल निवेशकों को आकर्षित करती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और भाषाओं को भी मंच देती है। मेरे लिए यह जुड़ाव केवल वाणिज्यिक नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सृजन का माध्यम भी है।

–हर्मन बावेजा

बावेजा ने कहा कि वे अगले 15 दिनों में एक बार फिर रायपुर आएंगे और इस परियोजना में भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी तीन फिल्में इस वर्ष रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण भी शामिल है।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बावेजा ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा, मैं भारत सरकार और इसकी नीतियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। हमारे देश की संप्रभुता सर्वोपरि है।

फिल्म सिटी परियोजना से जुड़े छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी इनिशिएटिव के प्रमुख श्री दिलराज सिन्हा ने बताया कि, फिल्म सिटी को अगले दो वर्षों में पूरी तरह से क्रियाशील बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्टेट-ऑफ-द-आर्ट शूटिंग फ्लोर, पोस्ट-प्रोडक्शन स्टूडियोज, एनीमेशन लैब, वीएफएक्स जोन, ओपन लोकेशन यूनिट्स, और फिल्म एवं मीडिया प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा। यह सिटी फिल्म टूरिज़्म और मीडिया निवेश के लिए भारत के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक बन सकती है। उन्होंने आगे बताया कि वे पूर्व में दुबई, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और श्रीलंका जैसे देशों में फिल्म परियोजनाओं के साथ कार्य कर चुके हैं और रायपुर में एक वैश्विक स्तर की फिल्म सिटी के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं।

हमारा उद्देश्य एक ऐसी संरचना खड़ी करना है जो स्थानीय प्रतिभा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जा सके और भारत के फिल्म मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को मजबूती से स्थापित कर सके।

– दिलराज सिन्हा

ग्रीन टेक सॉल्यूशन्स, मुंबई से जुड़े सिन्हा ने रायपुर की भौगोलिक और प्रशासनिक विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह शहर भविष्य की संभावनाओं से भरा हुआ है। यहां आधारभूत संरचनाएं, सरकार की इच्छाशक्ति और सांस्कृतिक विविधता—तीनों मौजूद हैं। यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बन सकता है। उनका मानना है कि इस परियोजना से हजारों रोजगार, सैकड़ों उद्यम, और अनगिनत रचनात्मक अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, यह राज्य के पर्यटन और होटल व्यवसाय को भी प्रोत्साहन देगा।

इस महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन के सफल आयोजन में मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरभि सिंह की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उन्होंने प्रेस आमंत्रण, आयोजन स्थल के समन्वय, और संवाद प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी कुशलता से निभाई।

यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब छत्तीसगढ़ को बॉलीवुड से एक नई पहचान मिल रही है। हम इसे केवल मीडिया कवरेज तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि यह राज्य की रचनात्मक क्रांति की शुरुआत है।

- सुरभि सिंह

छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म सिटी परियोजना में बॉलीवुड का जुड़ाव राज्य के लिए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। हर्मन बावेजा जैसे अनुभवी अभिनेता-निर्माता का समर्थन इस परियोजना को न केवल गति देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह कदम रोजगार, सांस्कृतिक संवर्धन, पर्यटन विकास और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार बन सकता है।

नक्सल प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी - श्री डेका

राज्यपाल श्री रमेन डेका से राजभवन में बस्तर क्षेत्र के कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिले के नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। श्री डेका ने नक्सल प्रभावितों को हर संभव मदद् देने की बात कही।

राज्यपाल श्री डेका ने सभी पीड़ितों से बात चीत की। शासन की ओर से नक्सल हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों को जो सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है उस राशि का सदुपयोग करने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की विशेष पहल पर केंद्र शासन द्वारा बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सतत् कार्रवाई की जा रही है तथा वर्ष 2026 तक इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाये जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर बस्तर क्षेत्र में विकास एवं पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित जो दिव्यांग हुए हैं उनको आत्म निर्भर बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नक्सल हिंसा से दिव्यांग हुए सुकमा जिले के ग्राम चिंता गुफा निवासी राहुल सोढ़ी का इलाज एम्स रायपुर में कराने के निर्देश दिये।

Shri Balaji Vidya Mandir

Managed by

ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR

46 YEARS OF EXCELLENCE

Admissions OPEN 2025-26

FOR NURSERY TO CLASS XII

The School of Quality
Education and Temple of Wisdom

Your kids Deserve
The best Education

Take Pride to
Admit your child in
one of the best schools
with
Quality Education

Branch Office

Contact Office Between

10:00 AM & 03.00 PM

Sec-II Devendra Nagar Raipur (C.G.)

Emaill: shribalajischoolraipur@gmail.com

Website : sbvmraipur.com

Shri Balaji Vidya Mandir

Managed by ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR
Basant Vihar Gate No.1 Near Basant Vihar
Garden, Gondwara Raipur (C.G.)
Time -10:00 AM & 03.00 PM

SBVM Kids Zone

Managed by ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR
Vijay Nagar, Behind Patel Cable, Bhanpur, Raipur

Time -10:00 AM & 01.00 PM

MOB: 9406400007, 9329128867

छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदायों की संस्कृति, जीवन शैली और लोक कला को समर्पित

राज्य का प्रथम

आदिवासी संग्रहालय

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, नवा रायपुर (अटल नगर)

संग्रहालय के प्रमुख आकर्षण

- संग्रहालय की कुल 14 गैलरियों में जनजातीय जीवनशैली के सभी पहलुओं का जीवंत प्रदर्शन
- जनजातियों के भौगोलिक विवरण, तीज-त्यौहार, पर्व-महोत्सव तथा विशिष्ट संस्कृति का चित्रण
- आवास एवं घरेलू उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र (परिधान) एवं आभूषण की अनुपम झलकियाँ
- कृषि तकनीक, उपकरणों व फसल मिंजाई का प्रदर्शन, जनजातीय नृत्यों एवं वाद्ययंत्रों का संग्रह
- आग जलाने, लौह निर्माण और रस्सी निर्माण की पारंपरिक जनजातीय तकनीक का प्रदर्शन
- कत्था निर्माण, चिवड़ा-लाई निर्माण, मंद आसवन, अन्न कुटाई- पिसाई व तेल प्रसंस्करण की प्रदर्शनी

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13265/32

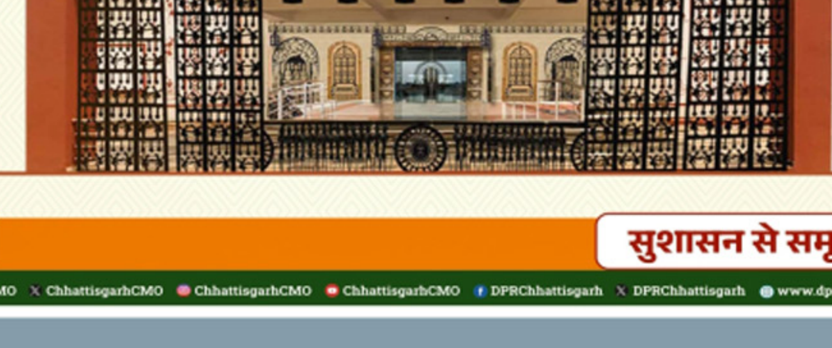

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in